बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन

बिजली विभाग का निजीकरण किसके लिए

बिजली एक अतिआवश्यक मूलभूत सुविधा है जो कि मानव को जानवरों से अलग करती है।

इसका उत्पादन निजी घराने भी करने लगे हैं जो अपेक्षाकृत महंगी पड़ती है।

अब सरकार इसका वितरण भी निजी हाथों में पीपीपी मॉडल के तहत देने जा रही है जो आम जनमानस को चंद पूंजी पतियों के हाथों में सौंपने जैसा होगा।

कोविड काल में विधुत विच्छेदन की कार्यवाही रोकते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की गई जबकि इसी दौरान निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं ने कोई राहत नहीं दी।

सार्वजानिक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा में लगे रहे जबकि प्राइवेट अस्पताल दूर से भी देखना नहीं चाहते थे।

जैसे जिओ ने फ्री से शुरुआत करके आज रिचार्ज महंगा कर दिया है वैसे ही निजी क्षेत्र में जाने पर बिजली के दाम आसमान छूने लगेंगे जो हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर देगी।

इस समय विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत वितरण एवं प्रसारण में सुधार किया जा रहा है जो कि आम जनता के टैक्स के पैसों हो रहा है। आम जनता के धन से सुधरा हुआ सिस्टम पूंजी पतियों को देना एक तरह से जनता के साथ धोखा देने जैसा प्रतीत हो रहा है।

बिजली रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही महत्वपूर्ण हो गई है जिसे कुछ लोगों के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

निजीकरण का एकं उद्देश्य कर्मचारियों की छटनी भी है। देश में युवा नौकरियों की तलाश में है और बिजली विभाग छटनी की तैयारी में, जरा सोचिए, ऐसे में युवाओं के भविष्य का क्या होगा।

ध्यान रहे निजीकरण से फायदा केवल चंद पूंजीपतियों का होगा न कि देश का।

बिजली विभाग को निजी क्षेत्र में सौंपने के मंसूबों को ध्वस्त करने को आगे आए, हमें आपके सहयोग की जरूरत है!

निवेदक बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन